THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Yes, Sir.

(b) Mobile telephone system with a capacity of 100 telephones has been introduced on an experimental basis in Delhi. This service can be availed in Delhi from a mobile telephone installed in the vehicle of the subscriber. Separate tariff has been prescribed for the service.

(c) 295 private subscribers have applied for the mobile telephones as on 17-4-1986.

(d) 51 subscribers have been provided with mobile telephones so far.

(e) Mobile telephones to remaining subcribers will only be provided after additional equipment is procured.

टेलीफोन विभाग में कदाचार

*5. **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली टेलीफोन के गाजियाबाद, शाहदरा पूर्व, 20, 21, लक्ष्मी नगर, दिल्ली गेट तथा ईदगाह टेलीफोन केन्द्रों में पिछले कई वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन लगाने तथा टेलीफोन मीटरों की काल रीडिंग के मामले में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेरा-फेरी को रोकने के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच करवाई है और उसका ब्यौरा क्या है, और यदि कोई जांच नहीं करवाई गई, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की अनियमितताएं विभाग के खासकर वे गिने-चुने अधिकारी करते है जिन्हें एक ही क्षेत्र में लम्बे अर्से तक तैनात किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भी कोई उच्च स्तरीय जांच करायी है और उन अधिकारियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

बेरोजगार स्नातकों को रसोई गैस के लिए एजेंसियों का आबंटन

*6. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

डा. बापू कालिदास :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 10 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1395 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 232 पेट्रोल पम्पों में से केवल 11 पम्प बेरोजगार स्नातकों को दिए गए और यदि हां, तो इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है ;

(ख) इस बारे में पूरे देश में और विशेषकर बिहार में विद्यमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में तथा दिल्ली में भी बेरोजगार युवकों को रसोई गैस की डीलरशिप देने के मामले में क्या नीति अपनायी है तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) दिल्ली संघ राज्य में इस समय एम.एस/एच.एस.डी. रिटेल आउटलेटों की कुल मिलाकर संख्या 232 है इसमें उस समय के स्थापित रिटेल आउटलेट भी शामिल है जब बेरोजगार स्नातकों/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों (यूजी/यूईजी) के लिए आरक्षण नहीं था । इनमें से 11 रिटेल आउटलेट बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए आई.ओ.सी. की योजना जो वर्ष 1970 और 1971 में चालू थी, के अन्तर्गत दिये गये थे । 1982-83 से अपनाई गई नीति में इस श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है । इसका अनुपालन किया जा रहा है ।

(ख) 1982-83 और 1985-86 के बीच देश में कुल योजित 1914 रिटेल आउटलेटों में से 456 यू.जी/यू.ई.जी. श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए । बिहार के सम्बन्ध में इनकी संख्या क्रमश: 175 और 45 है ।